समक्ष महिंदर सिंह सुल्लर जे.

राज *कुमार- याचिकाकर्ता*

बनाम

विकास गौतम और अन्य- *प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपीनं. 2009 का 265

29 नवंबर 2010

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 91 और 451- याचिकाकर्ता द्वारा ट्रक खरीदने के लिए वित्त कंपनी से ऋण लेना - किराया-खरीद समझौता - याचिकाकर्ता नियमित रूप से किश्तों का भुगतान करना - कंपनी याचिकाकर्ता के कब्जे से जबरन ट्रक छीनना - याचिकाकर्ता आपराधिक शिकायत दर्ज करना - चाहे याचिकाकर्ता आपराधिक मुकदमा लंबित रहने के दौरान ट्रक को कब्जे में लेने का हकदार कार्यवाही - आयोजित, हां - प्रतिवादियों को कानूनी रूप से कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती - याचिका की अनुमति दी गई, मामला सीआरपीसी की धारा 451 के साथ पठित धारा 91 के तहत आवेदन पर नये सिरे से निर्णय लेने के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया।

माना गया कि ट्रायल मजिस्ट्रेट इस प्रासंगिक संदर्भ में गहरी कानूनी त्रुटि में फंस गया है। जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवेदन दायर करने का अवसर दिया। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर 2002 के *समझौते के तहत* प्रतिवादी संख्या 5 से ऋण उधार लिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने पहले ही देय किश्तों का भुगतान कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रतिवादियों ने अवैध रूप से और जबरन उसका ट्रक छीन लिया है। इसलिए, तथ्यात्मक मैट्रिक्स विवाद में नहीं है। एक बार, प्रश्नगत ट्रक को उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के कब्जे से जबरन छीन लिया गया था, उस स्थिति में, याचिकाकर्ता इसकी क्षतिपूर्ति का हकदार है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक बार यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के कब्जे से ट्रक को जबरन छीन लिया है, तो स्वाभाविक रूप से वह आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इसके कब्जे का हकदार है, 'केवल यह तथ्य कि ट्रक बेचा गया था, संभवतः नहीं हो सकता आपराधिक न्याय प्रशासन के रास्ते में खड़े होने की अनुमति दी जाएगी और उत्तरदाताओं की संकेतित अवैध कार्रवाई की किसी भी तरह से सराहना और प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता है। आपराधिक न्यायालय इस संदर्भ में असहाय नहीं हैं।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश चौधरी ।

राहुल गर्ग, वकील, अश्वनी तलवार के लिए, वकील, *प्रतिवादी नंबर I से 4 के लिए।*

सिद्धार्थ सरूप, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

महिंदर सिंह सुल्लर, जे. (मौखिक)

(1) तथ्यों का मैट्रिक्स, जिसे इस पुनरीक्षण याचिका में शामिल मुख्य विवाद को तय करने और रिकॉर्ड से निकलने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, याचिकाकर्ता-राज कुमार, साधु राम के पुत्र, ने एम से ऋण उधार लिया था। /एस अशोका लीलैंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (अब इंडसलैंड बैंक लिमिटेड में विलय) - प्रतिवादी संख्या 5, एक ट्रक के चेसिस की खरीद के लिए, 16 अक्टूबर, 2002 के ऋण समझौते के आधार पर। इसकी बॉडी का निर्माण करने और इसे चेसिस पर फिट करने के बाद, याचिकाकर्ता ने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने नियमित रूप से प्रतिवादी संख्या 5 को समय पर ऋण की देय किश्तों का भुगतान किया।

(2) याचिकाकर्ता का मामला आगे बढ़ता है कि 28 जनवरी, 2005 को उसका ट्रक नेपाल जाने के लिए बुक किया गया था। 29 जनवरी, 2005 को जैसे ही वह अपने ट्रक के साथ गांव मोहरी, जिला अम्बाला के पास पहुंचा, इसी बीच अशोक लीलैंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक रवि कुमार गुप्ता (प्रतिवादी नंबर 3) ने ट्रक को रोक लिया और 5-6 अन्य, जो अपना चेहरा ढंके हुए थे, रिवॉल्वर और

अन्य घातक हथियारों से लैस होकर भी घटनास्थल पर दिखाई दिए। उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के कहने पर अवैध रूप से और जबरन याचिकाकर्ता का ट्रक छीन लिया और उसे प्रतिवादी नंबर 4 के परिसर में खड़ा कर दिया। मामले की सूचना पुलिस स्टेशन, शाहबाद की पुलिस को दी गई। चूंकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए याचिकाकर्ता ने एक शिकायत दर्ज की, जिसे मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेज दिया, जिसके आधार पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस स्टेशन शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र की पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 219 दिनांक 24 जुलाई 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया था । इसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी के खिलाफ कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की।

(3) पुलिस की कार्रवाई से दुखी होकर, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष एक विरोध याचिका (शिकायत) दायर की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को धारा 392, 506 और 120-बी आईपीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। दावा किया गया कि एफआईआर अभी तक रद्द नहीं की गई है, आरोपियों को बरी नहीं किया गया है और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित है। हालाँकि, ट्रक एक केस प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसे पुलिस या अदालत ने अपने कब्जे में नहीं लिया था, जिससे याचिकाकर्ता को इस प्रासंगिक संबंध में एक आवेदन दायर करने की आवश्यकता पड़ी। इस पर निर्णय नहीं लिया गया और बाद में याचिकाकर्ता ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया कि आवश्यक राहत के लिए वह पहले ही उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर कर चुका है। इस न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका का निपटारा कर दिया गया और याचिकाकर्ता को इस प्रासंगिक संबंध में नया आवेदन दायर करने की छूट दी गई।

(4) नतीजतन, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 451 के साथ पठित धारा 91 के तहत ट्रक को पेश करने और सुपरदारी पर रिहा करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसे ट्रायल मजिस्ट्रेट ने 8 दिसंबर, 2008 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया था।

(5) याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ और उसने विवादित आदेश को रद्द

करने के लिए तत्काल याचिका दायर की। इस प्रकार, मैं इस मामले को समझ गया हूँ।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने, उनकी बहुमूल्य मदद से रिकॉर्ड का अध्ययन करने और पूरे मामले पर गहराई से विचार करने के बाद, मेरी राय में, यह याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

(7) यहां जो विवादित नहीं है वह यह है कि, याचिकाकर्ता ने ट्रक के चेसिस की खरीद के लिए प्रतिवादी नंबर 5 से ऋण उधार लिया है और लगभग रु। इसकी बॉडी पर उन्होंने अपनी जेब से 2,50,000 रुपये खर्च किए और इसे सड़क के लायक बनाया। कहा गया कि प्रतिवादियों ने ऊपर बताए गए तरीके से 29 जनवरी, 2005 को अवैध रूप से उससे ट्रक छीन लिया। याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 451 के साथ पठित धारा 91 के तहत दायर आवेदन को ट्रायल मजिस्ट्रेट ने 8 दिसंबर, 2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। *जिसका* ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार है : -

> *"इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज कुमार की शिकायत पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392. 506 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने गहन जांच के बाद रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की है। आरोपियों को तलब किया गया है शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर। इस स्तर पर, यह बताना मुश्किल है कि क्या आरोपी व्यक्तियों ने ट्रक संख्या HR-65-0475 को जबरन और अवैध रूप से छीन लिया और कोई अपराध किया। उक्त ट्रक की आवश्यकता नहीं है किसी भी उद्देश्य के लिए अदालत। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के साथ पठित धारा 91 के तहत हाथ में लिया गया एक आवेदन गलत है और विचारणीय नहीं है। मामले को शिकायत मामले के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और दोनों पक्षों को अपना मामला साबित करना है। दोनों पार्टियां संबंधित ट्रक पर कब्जे का दावा कर रही हैं। लेकिन इस स्तर पर, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि वैध दावेदार कौन है। 'ट्रक पर पहले ही आरोपी/प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उनके*

द्वारा बेच दिया गया है। ट्रक को इसके तहत नहीं मांगा जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91. आगे,

शिकायतकर्ता ने ट्रक की पेशी के लिए दिनांक 22 जनवरी, 2007 को एक आवेदन दायर किया, जिसे शिकायतकर्ता ने 23 अक्टूबर, 2007 को वापस ले लिया। आपराधिक विविध। याचिका जीवनी. 2007 की 47759-एम भी शिकायतकर्ता द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे 4 सितंबर, 2008 को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था। इससे पहले ट्रक नंबर एचआर-65-0475 को रिहा करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। अदालत और उसके बाद माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष यह अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है और अब फिर से शिकायतकर्ता ने हाथ में आवेदन दिया है। इस आधार पर भी शिकायतकर्ता इस स्तर पर राहत का हकदार नहीं है। "

(8) इसका मतलब यह है कि आवेदन को खारिज करने में मुख्य आधार, जो ट्रायल मजिस्ट्रेट के साथ विचार-विमर्श किया गया प्रतीत होता है, वह यह है कि (i) यह तय होना बाकी है कि क्या आरोपी व्यक्तियों ने ट्रक को जबरन और अवैध रूप से छीन लिया था, (ii) उक्त किसी भी उद्देश्य के लिए अदालत को ट्रक की आवश्यकता नहीं है, (iii) इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि वैध दावेदार कौन है, (iv) 2007 के सीआरएम नंबर एम-47759 को वापस ले लिया गया और (v) आगे बढ़ाते हुए खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष ट्रक को रिहा करने के लिए आवेदन करना कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

(9) पार्टियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, ट्रायल मजिस्ट्रेट इस प्रासंगिक संदर्भ में एक गहरी कानूनी त्रुटि में फंस गया है। जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवेदन दायर करने का अवसर दिया। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर, 2002 के समझौते *के तहत* प्रतिवादी संख्या 5 से ऋण उधार लिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने पहले ही देय किश्तों

का भुगतान कर दिया है, लेकिन फिर भी उत्तरदाताओं ने अवैध रूप से और जबरन छीन लिया है उसका ट्रक. इसलिए, तथ्यात्मक मैट्रिक्स विवाद में नहीं है। एक बार, प्रश्नगत ट्रक को याचिकाकर्ता के कब्जे से उत्तरदाताओं द्वारा जबरन छीन लिया गया था, उस स्थिति में, वह (याचिकाकर्ता) इसकी क्षतिपूर्ति का हकदार है।

(10) हालाँकि, प्रतिवादियों के विद्वान वकील का मशहूर तर्क कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पूरी ऋण राशि का भुगतान नहीं किया था, ट्रक को उनके द्वारा सही तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया था, न केवल योग्यता से रहित है बल्कि गलत भी है। तर्कों के आधार पर मान लें (हालांकि स्वीकार नहीं किया गया है), यदि किश्तों की कुछ राशि का भुगतान करना बाकी है याचिकाकर्ता, तो उत्तरदाताओं के पास समझौते के अनुसार, राशि की वसूली के लिए अपना प्रभावकारी नागरिक उपाय है। लेकिन क़ानूनी तौर पर उन्हें क़ानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. एक बार, यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के कब्जे से ट्रक को जबरन छीन लिया है, तो स्वाभाविक रूप से वह आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ट्रक को अपने कब्जे में लेने का हकदार है। केवल यह तथ्य कि ट्रक बेचा गया था, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किया गया था, को संभवतः आपराधिक न्याय प्रशासन के रास्ते में खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और प्रतिवादियों की संकेतित अवैध कार्रवाई को किसी भी तरह से सराहा और प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। फौजदारी अदालतें इस संदर्भ में असहाय नहीं हैं।

(11) **मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** *बनाम* **प्रकाश कौर और अन्य के** [1]मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न उठा । किराया खरीद समझौते के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह फैसला सुनाया गया कि, "हम देश में कानून के शासन द्वारा शासित हैं। ऋण की वसूली या वाहनों की जब्ती केवल कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है। बैंक बलपूर्वक कब्जा लेने के लिए गुंडों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे मामलों में, जहां उधारकर्ता ने किश्तों के भुगतान में चूक की हो, बैंक को मजबूत हथियार का सहारा लेने के बजाय, वाहनों को अपने कब्जे में लेने के लिए कानून द्वारा

[1] 2007 (2) आईएलसी.आर. (आपराधिक) 76 .

मान्यता प्राप्त प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। गुंडों की रणनीति।" उपर्युक्त निर्णय *"म्यूटैटिस-मुआइंडिस* " वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का संपूर्ण उत्तर है। इसलिए, मेरा मानना है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(12) इसके अलावा, मुख्य आपराधिक शिकायत और रद्दीकरण रिपोर्ट अभी भी पिछले लगभग पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित है और उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसका कारण ट्रायल मजिस्ट्रेट को सबसे अच्छी तरह पता है।

(13) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर और कुछ टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि मामले के नए निर्णय के दौरान दोनों पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तत्काल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। 8 दिसंबर, 2008 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया गया है, ताकि याचिकाकर्ता द्वारा नए सिरे से दायर धारा 91 के साथ पठित धारा 451 सीआरपीसी के आवेदन पर यथासंभव कानून के अनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ-साथ मुख्य मामला भी में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा